ऐतिहासिक शहरों का विकास

रतीश नंदा

भारत के राष्ट्रीय स्मारक देश और इसके नागरिकों के लिये अनमोल और महत्वपूर्ण धरोहर हैं। इनके साथ हमारे भावनात्मक, धार्मिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, वास्तुशिल्पीय और पुरातात्विक मूल्य जुड़े हुए हैं। इन स्मारकों के संरक्षण के काम में पारंपरिक सामग्रियों, औजारों और भवन निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले कारीगरों की जरूरत होती है। लिहाजा, स्मारकों के संरक्षण की रोज़गार पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सौभाग्य से, पश्चिम के विपरीत हम भारतीय अपनी शिल्प परंपराओं को मौजूदा समय में बचाने में कामयाब रहे हैं। बेहतर होगा कि संरक्षण के साथ ही आधुनिक सार्वजनिक इमारतों में भी शिल्प आधारित दृष्टिकोण पर जोर दिया जाये।

भारत को पारंपरिक वास्तु शिल्प में झलकने वाली अपनी हजारों वर्षों की निर्मित विरासत और जीवित संस्कृति पर गर्व है। इक्कीसवीं सदी में हमें इस विरासत के संरक्षण के लिये सही मायनों में भारतीय नज़रिये के बारे में सोचने की जरूरत है। यह नज़रिया ऐसा होना चाहिये जिसमें ऐतिहासिक धरोहरों का इस्तेमाल हमारे पुराने शहरों के निवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिये किया जा सके।

संरक्षण और परिरक्षण के प्रयासों को सार्वजनिक नीतियों और विकास की योजनाओं से जोड़े जाने से हमारे अनेक ऐतिहासिक शहरों के निवासियों को लाभ होगा। आगा खान संस्कृति न्यास (एकेटीसी) ने इस नज़रिये को अपनाते हुए भारतीय पुरातत्व संरक्षण (एएसआई), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सहयोग से हुमायूं का मक़बरा-निज़ामुद्दीन क्षेत्र में 15 वर्षीय शहरी नवीकरण परियोजना चलायी है। इस परियोजना में संरक्षण के प्रयासों में रोज़गार सृजन, इलाके के शिल्पों और कलाओं को प्रोत्साहन, अवसंरचना निर्माण, पर्यावरण का बचाव और सौंदर्यीकरण के जरिये स्थानीय क्षेत्र विकास को भी शामिल किया गया है।

एएसआई ने हमारी राष्ट्रीय विरासतों का दीर्घकालिक और संवहनीय संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये कई कदम उठाये हैं। वह हमारी विरासत के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। एएसआई संरक्षण के प्रयासों में सिविल सोसायटी की भागीदारी बढ़ाने के लिये भी प्रयासरत है। पिछले दो दशकों में ऐतिहासिक स्थलों के मूल चरित्र को बरकरार रखने के लिये उनके शहरी विन्यास के महत्व के प्रति जागरुकता बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप 1992 में दिशानिर्देश जारी किये गये और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) का गठन हुआ। एनएमए को हरेक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक के विन्यास में नयी इमारतों के लिये दिशानिर्देश तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। इन दिशानिर्देशों को प्रतिबंधात्मक बनाये जाने के बजाय इनमें सुधार के उपायों और ऐसे प्रोत्साहनों पर जोर दिया जाना चाहिये जिनसे ऐतिहासिक शहरी परिवेश में सुधार होने के साथ ही स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़े।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हमारे देश की विरासत का दीर्घकालिक सतत संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रहा है

लेखक संरक्षण वास्तुकार और आगा खान सांस्कृतिक न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ईमेल : ratish.nanda@akdn.org

90 एकड़ के सुंदर नर्सरी पार्क में 2021 में 7 लाख से अधिक आगंतुक आए। यहां स्थित छह यूनेस्को विश्व विरासत संरचनाओं, 30 एकड़ जंगल क्षेत्र, एम्फीथिएटर और बच्चों के खेलने के क्षेत्र जैसी सुविधाएं इस पार्क को दिल्ली के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक बनाती है

भारत की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1997 में विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा के परिसर में बाग के उद्धार का काम शुरू किया गया। परियोजना 2003 में पूरी हुई तथा मुगल गार्डन और जल प्रवाह के उद्धार के बाद कुछेक महीनों में ही हुमायूं के मकबरे में आने वालों की संख्या में 1000 प्रतिशत का इजाफा हो गया। बाग के उद्धार की सफलता के बाद भारत सरकार ने एकेटीसी से भारत में और काम अपने हाथ में लेने के लिये कहा। इस बात पर सहमति बनी कि एकेटीसी बाग के उद्धार को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी शहरी नवीकरण परियोजना शुरू करेगा। इस परियोजना में अनेक स्मारकों का संरक्षण शामिल होगा। इसके साथ ही नजदीकी हजरत निज़ामुद्दीन बस्ती के निवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये कदम उठाये जायेंगे। परियोजना में पर्यावरण की बहाली के लिये 200 एकड़ से ज्यादा के डिस्ट्रिक्ट पार्क का सौंदर्यीकरण भी शामिल था।

पुरातत्व के लिहाज से हुमायूं के मकबरे को इससे ज्यादा प्रसिद्ध ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। इस मकबरे को एक सदी से ज्यादा समय तक अनुपयुक्त संरक्षण कार्यों के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा। मकबरे की छत से 10 लाख किलो कंक्रीट हटाये जाने की आवश्यकता थी। इस कंक्रीट को 20वीं सदी में बारिश के पानी का रिसाव रोकने के लिये डाला गया था। इसी तरह दो लाख वर्ग फीट से ज्यादा सीमेंट प्लास्टर को हटा कर उसकी जगह पारंपरिक चूने का पलस्तर लगाये जाने की जरूरत थी। इमारत के मूल दरवाजों को 20वीं सदी में ही जलावन की लकड़ी बना लिया गया था। इसके अलावा मकबरे के अंदरूनी हिस्से की टाइलों को हटा कर पलस्तर कर दिया गया था।

भारत के अनेक अन्य स्मारकों का भी यही हाल था। अनुपयुक्त आधुनिक सामग्री से की गयी मरम्मत से मूल डिज़ाइन नष्ट होने के साथ ही उनके क्षय की प्रक्रिया भी तेज हो गयी। एएसआई की सहमति से एकेटीसी ने हुमायूं के मकबरे के लिये जो संरक्षण योजना तैयार की उसके तहत पहले की गयी अनुपयुक्त मरम्मत को हटाया जाना था। उसकी जगह पारंपरिक सामग्रियों और निर्माण तकनीकों तथा कुशल कारीगरों के जरिये प्रामाणिक मरम्मत की जानी थी।

हमारे पूर्वजों ने पत्थर, मिट्टी, बांस, लकड़ी और ईंट जैसी पारंपरिक निर्माण सामग्रियों के उपयोग से शानदार इमारतें बनायी हैं। इनमें अद्भुत शहरों में छोटे मकानों से लेकर भव्य महल, मठ, मंदिर, मकबरे और स्तूप शामिल हैं। सिर्फ कुछेक दशक पहले की इमारतों की भारतीय शहरों में वर्तमान में कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे भवनों से तुलना कर यह समझना आसान नहीं है कि हमने डिज़ाइन और शिल्प की अपनी क्षमताओं को सीमेंट, इस्पात और शीशा जैसी सामग्रियों के आसानी से उपलब्ध होने के कुछ वर्षों के अंदर ही कैसे गंवा दिया। पारंपरिक छोड़ सस्ते आधुनिक को अपनाने के क्रम में हम उन वास्तु कौशलों से हाथ धो बैठे जिनमें लाखों कार्य दिवस का रोज़गार पैदा करने की क्षमता थी। ये वास्तु कौशल यह भी सुनिश्चित करते थे कि हमारे शहरों की पहचान अनूठी और जीवन की गुणवत्ता ऊंची हो।

एएसआई ने हमारी राष्ट्रीय विरासतों का दीर्घकालिक और संवहनीय संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये कई कदम उठाये हैं। वह हमारी विरासत के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। एएसआई संरक्षण के प्रयासों में सिविल सोसायटी की भागीदारी बढ़ाने के लिये भी प्रयासरत है।

संरक्षण के काम में पारंपरिक सामग्रियों, औजारों और भवन निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले कारीगरों की जरूरत होती है। लिहाजा, रोज़गार पैदा करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सौभाग्य से, पश्चिम के विपरीत हम भारतीय अपनी शिल्प परंपराओं को मौजूदा समय में बचाने में कामयाब रहे हैं। बेहतर होगा कि हम संरक्षण के साथ ही आधुनिक सार्वजनिक इमारतों में भी शिल्प

आधारित दृष्टिकोण पर जोर दें। संगतराश, पलस्तरकार, राजमिस्त्री, बढ़ई और ईंट बनाने वाले जैसे कारीगर अपने पूर्वजों के काम की नकल करने में काफी गर्व महसूस करते हैं। भवन संरक्षण में उनकी अग्रणी भूमिका से मूल निर्माताओं की डिज़ाइन का सम्मान होगा। इससे आगंतुकों में हमारी निर्मित विरासत के महत्व की समझ और दिलचस्पी बरकरार रहेगी। इसके साथ ही शिल्पकार एक बार फिर से संरक्षण के काम में हितधारक बनेंगे। वे अपनी उस अगली पीढ़ी को पारंपरिक कौशलों का प्रशिक्षण देना जारी रखेंगे जो बड़ी संख्या में अन्य उद्यमों की ओर पलायन कर रही है।

भारत के राष्ट्रीय स्मारक देश और इसके नागरिकों के लिये अनमोल और महत्वपूर्ण धरोहर हैं। इनके साथ हमारे भावनात्मक, धार्मिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, वास्तुशिल्पीय और पुरातात्विक मूल्य जुड़े हुए हैं। लेकिन शहरीकरण के दबाव से इन धरोहरों पर खतरा मंडरा रहा है। संरक्षण और विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिये सरकार की विभिन्न एजेंसियों को शैक्षिक संस्थानों, सिविल सोसायटी और स्थानीय समुदायों को भागीदार बनाना चाहिये। इस तरह के प्रयासों में संसाधनों के किसी भी निवेश से कई फायदे मिलने के अलावा सरकार के अनेक लक्ष्य भी पूरे होते हैं।

निज़ामुद्दीन शहरी नवीकरण की सफलता ने समुदाय आधारित संरक्षण का एक आदर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। घनी आबादी वाली हजरत निज़ामुद्दीन बस्ती में अनेक संरक्षित इमारतों के संरक्षण के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्यसेवाएं और स्वच्छता मुहैया कराने के कदम उठाये गये हैं। स्थानीय युवाओं और महिलाओं को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इलाके के पार्कों का सौंदर्यीकरण और गलियों में सुधार किया गया है। इसके अलावा सूफीवाद और कव्वाली के इर्दगिर्द केंद्रित 700 साल पुरानी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये स्थल तैयार किये गये हैं।

ऐतिहासिक शहरों में हमारे अनेक स्मारक घनी आबादी के बीच में हैं। घनी बस्तियों में इन इमारतों के आसपास रहने वाले लोग अक्सर गरीब और बुनियादी शहरी अवसंरचना से वंचित होते हैं। निज़ामुद्दीन शहरी नवीकरण की सफलता ने समुदाय आधारित संरक्षण का एक आदर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। घनी आबादी वाली हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती में अनेक संरक्षित इमारतों के संरक्षण के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्यसेवाएं और स्वच्छता मुहैया कराने के कदम उठाये गये हैं। स्थानीय युवाओं और महिलाओं को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इलाके के पार्कों का सौंदर्यीकरण और गलियों में सुधार किया गया है। इसके अलावा सूफीवाद और कव्वाली के इर्दगिर्द केंद्रित 700 साल पुरानी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये स्थल तैयार किये गये हैं। उम्मीद है कि हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती के निवासी अपने इलाके की निर्मित विरासत के संरक्षण में अब केंद्रीय भूमिका निभायेंगे। भारत में इस तरह के अन्य ऐतिहासिक शहरी क्षेत्रों में विकास के लिये संरक्षण और संस्कृति को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

संरक्षण आधारित विकास के निज़ामुद्दीन मॉडल को दोहराने के लिये सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसके लिये गैरसरकारी संगठनों, निवासी कल्याण संघों, अनुदान देने वाली संस्थाओं, कॉरपोरेट क्षेत्र तथा नगर पालिकाओं और निगमों को दीर्घकालिक दृष्टि के साथ एकजुट होना होगा। वैश्विक उदाहरण बनने वाली यह पहल इसलिये कामयाब हो सकी कि इसकी सफलता के लिये एक बहुविषयक टीम ने संरक्षित और अच्छे रखरखाव वाली विरासतों के साथ ही निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये अनुकूलित, प्रासंगिक और स्थानीय समाधान तैयार किये।

14वीं शताब्दी के निज़ामुद्दीन बावली का दृश्य, जो चारों ओर ऐतिहासिक स्मारकों के बीच स्थित है। जुलाई 2008 में इसके ढहने के बाद यहाँ बड़ा शहरी संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत इस संरचना के संरक्षण के अलावा परिसर में 10 से अधिक अन्य स्मारक का पुनरुद्धार किया गया। शताब्दियों बाद पहली बार इसका पानी साफ किया गया, और बस्ती के युवाओं को क्षेत्र में हेरिटेज वॉक संचालित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

कई लोकप्रिय स्थलों पर मौजूदा इमारतों के अंदर ही या संवेदनशीलता से डिज़ाइन किये गये नये भवनों में संग्रहालय या विवेचना केंद्र खोलने की जरूरत महसूस की जा रही है। आगंतुकों के अनुभव की समृद्धि और नयी पीढ़ी को प्रमुख स्थलों और स्मारक समूहों की ओर आकृष्ट करने के मकसद से नयी मीडिया के इस्तेमाल से आधुनिक डिस्प्ले लगाने की योजना बनायी गयी है। विश्व भर के उदाहरणों से जाहिर है कि महत्वपूर्ण आधुनिक स्थापत्य से विरासत स्थलों की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ ही इनमें आगंतुकों की दिलचस्पी पैदा होती है। एकेटीसी मौजूदा समय में हुमायूं के मकबरे और हैदराबाद के गोलकोंडा में कुतुबशाही मकबरे में संग्रहालयों का निर्माण कर रहा है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इन दोनों परियोजनाओं के लिये धन मुहैया कराया है।

संरक्षण और विकास को साथ-साथ चलना चाहिये। लेकिन ऐसे किसी भी विकास के संवहनीय और दीर्घकालिक होने के लिये संरक्षण को सबसे ऊपर रखे जाने की जरूरत है। ■